RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 28 JULY TO 03 AUGUST 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 49 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एमएसएमई कंपनियों को 45 दिन में बकाये का भुगतान कर देगा केंद्र Page 3

भारत का पहला कस्टमाइज़्ड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और वेलनेस ब्रांड, वैदिक्स् Page 4

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ऑडी की शुरूआत लांच की तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी Page 7

editoria!

करदाताओं को सम्मान

वित्त मंत्री निर्मला सीता सीतारमण ने कहा है कि ईमानदारी से आयकर देनेवाले लोगों को आदर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे देश की प्रगति में अपना योगदान कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि 1.30 अरब से अधिक की आबादी के हमारे देश में 2020 में आयकर देनेवालों की संख्या लगभग 1.46 करोड़ ही थी. इनमें से 46 लाख लोगों ने ही अपनी आमदनी 10 लाख रुपये सालाना से अधिक बतायी थी. पिछले वित्त वर्ष में जनवरी के मध्य तक लगभग 5.95 करोड़ लोगों ने अपनी आय का ब्यौरा दिया था. यह संख्या 2019-20 की तुलना में करीब पांच फीसदी ज्यादा है. इन लगभग छह करोड़ में से अधिकतर लोगों को विभिन्न छूटों की वजह से आयकर नहीं देना होता है. आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर सरकारी राजस्व में अहम भूमिका निभाते हैं. जो लोग आयकर की सीमा में आते हैं, उनसे यह अपेक्षा रहती है कि वे सही जानकारी देंगे और उसके मुताबिक कर चुकायेंगे. यह सच है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब और निम्न आय वर्ग में है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से लोग कर देने से बचने के लिए या तो ठीक से ब्यौरा नहीं देते या फिर आय के स्रोत के रूप में ऐसे व्यवसायों का उल्लेख करते हैं, जो कराधान के दायरे से बाहर हैं. बीते डेढ़ साल के महामारी के दौर में जहां आमदनी में कमी आयी है, वहीं राजस्व संग्रहण भी प्रभावित हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने आय के अनुसार समुचित कर दिया है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए. कोरोना काल को छोड़ दें, तो आर्थिक मोर्चे पर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति होती रही है. निरंतर विकास को देखते हुए यह स्वीकार कर पाना कठिन है कि देश में केवल डेढ़ करोड़ लोग ही ऐसे हैं, जिन्हें आयकर देना चाहिए. आय छुपाने और कर चुराने की प्रवृत्ति किस कदर हावी है, इसका अनुमान अक्सर पड़नेवाले आयकर छापों से लगाया जा सकता है. बीते डेढ़ दशक से अधिक अवधि में करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी 22 प्रतिशत के आसपास ही रही है. इसके बावजूद वर्तमान संख्या बहुत कम है. इस संदर्भ में एक बड़ी विसंगति यह है कि वेतन पानेवाले करदाता गैर-वेतन आयवाले लोगों की तुलना में तीन गुना से अधिक कर चुकाते हैं. उनके पास अपनी आमदनी को छुपाने का कोई रास्ता भी नहीं होता. यह भी उल्लेखनीय है कि कुल कर राजस्व संग्रहण का 60 प्रतिशत हिस्सा मात्र चार प्रतिशत करदाता देते हैं. कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ब्यौरा और कर देने की प्रक्रिया में लगातार सुधार को प्राथमिकता दे रही है. डिजिटल तकनीक पर आधारित सुविधाओं के बढ़ने से अब करदाताओं को कर चुकाने, अधिक राशि को वापस लेने या शिकायतों का निवारण करने के लिए आयकर कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है. इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है. ऐसे में लोगों को कर देने में उत्साह दिखाना चाहिए.

एक अगस्त से आपकी जेब पर पड़ने वाला है भारी बोझ, बदल जाएंगे ये नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और 1 अगस्त से आपके दैनिक जीवन से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। एक अगस्त से बैंक से नकद निकासी और चेक बुक के नियम बदलने जा रहे हैं। अब इन सेवाओं के लिए आपको को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप तय सीमा से ज्यादा बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा एक अगस्त से रसोई गैस की नई कीमतें भी जारी होंगी, इसका सीधा असर आपकी घर के बजट पर पड़ता है।

ATM इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी

1 अगस्त 2021 से एटीएम से तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर ज्यादा पैसे देने होंगे। इंटरचेंज फीस को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर सकते हैं। वहीं नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरचेंज फीस को 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर सकते हैं। आरबीआई इसकी इजाजत पिछले माह दे चुका है। आपको बता दें बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिये एटीएम लगाते हैं और दूसरे बैंकों के ग्राहकों को भी इसके जरिए सेवाएं दी जाती हैं। निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग के एवज में वे शुल्क लेते हैं जिसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। आरबीआई का कहना है कि एटीएम लगाने की बढ़ती लागत और एटीएम परिचालकों के रखरखाव के खर्च में वृद्धि को देखते हुए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

डोरस्टेप बैंकिंग पर लेगा IPPB चार्ज

1 अगस्त 2021 से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) अपने ग्राहकों से डोरस्टेप बैंकिंग (Doorstep Banking) के लिए चार्ज लेने वाला है। अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) डोरस्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है लेकिन 1 अगस्त से बैंक अपने हर ग्राहक से डोरस्टेप बैंकिंग के मामले में चुनिंदा प्रॉडक्ट/सर्विसेज के लिए हर रिक्वेस्ट पर 20 रुपये प्लस जीएसटी वसूलेगा। जो लोग IPPB के ग्राहक नहीं हैं लेकिन IPPB की डोरस्टेप बैंकिंग के तहत कुछ सर्विस का लाभ लेते हैं, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा।

1 अगस्त से बैंक हॉलिडे पर मिलेगी सैलेरी

2021 से रविवार या कोई दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं रुकेगा, यानी तय डेट पर ही सैलरी और पेंशन का भुगतान हो जाएगा। दरअसल, रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (National Automated Clearing House-NACH) सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित NACH के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि की भुगतान होता है। एक अगस्त से NACH की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफर कर सकेंगी।

जारी होंगी सिलेंडर की नई कीमतें

1 अगस्त से थ्ह्ड सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं।

एक अगस्त से लगने वाला चार्ज

- IPPB खातों में फंड ट्रान्सफर पर 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- दूसरे बैंक खातों में फंड ट्रान्सफर पर 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- सेंड मनी सर्विस के तहत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पीओएसबी स्वीप इन और पीओएसबी स्वीप आउट के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- बिल पेमेंट्स के तहत मोबाइल पोस्टपेड और बिल पेमेंट के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- सर्विस रिक्वेस्ट्स के मामले में अकाउंट सर्विसेज के तहत क्यूआर कोड रिइश्यू के लिए चार्ज 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- असिस्टेड यूपीआई के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी।
- कैश विदड्रॉअल और कैश डिपॉजिट के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी।

रणनीतिः पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार करेगी रिजर्व कच्चे तेल का इस्तेमाल, सस्ता होगा ईंधन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने रिजर्व कच्चे तेल के इस्तेमाल की रणनीति बनाई है। इससे वैश्विक बाजार में महंगे क्रूड के आयात से बचने के साथ घरेलू बाजार में भी ईंधन सस्ता करने में मदद मिलेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत अपने कुल तेल भंडार का 50इ वाणिज्यिक इस्तेमाल करेगा। इसके तहत 3.65 करोड़ बैरल क्रूड (50 लाख टन) तेल शोधन कंपनियों को कम कीमत पर दिया जाएगा। तेल की बिक्री से मिले फंड का इस्तेमाल और रिजर्व टैंक बनाने में होगा। साथ ही कंपनियों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव भी घटेगा और क्रूड के सस्ता होने पर वे दोबारा बड़ी मात्रा में आयात करेंगी।

गौरतलब है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) व अन्य सहयोगी देशों की ओर से क्रूड उत्पादन में प्रतिदिन 70 लाख बैरल कटौती किए जाने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम 77.84 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए। इसके बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देशों ने अपने भंडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब भारत भी इसमें शामिल हो रहा है।

15 लाख टन क्रूड का निर्यात करेंगी कंपनियां

रिजर्व तेल का प्रबंधन करने वाली कंपनी इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने स्थानीय खरीदारों को 10 लाख टन कच्चा तेल बेचने की अनुमति दी है। निजी क्षेत्र की कंपनियों ने आयात किए 15 लाख टन क्रॅड को वापस वैश्विक बाजार में निर्यात की रणनीति बनाई है, क्योंकि भारतीय तेल शोधन कंपनियां इस महंगे क्रूड का इस्तेमाल नहीं करेंगी।

जून में नौ महीने का सबसे कम आयात

भारत ने जून में पिछले नौ महीने में सबसे कम क्रूड का आयात किया है। 2021 में अब तक कच्चे तेल के दाम 44इ बढ़ चुके हैं। पिछले दिनों भारत ने सऊदी अरब से उत्पादन बढ़ाकर कीमतें थामने की गुहार लगाई थी। इस पर अरब ने पिछले साल सस्ती दरों पर खरीदे तेल का इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी, जिस पर अब अमल शुरू हो गया है।

लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल स्थिर, कच्चा तेल फिर 74 डॉलर के पार

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे कोविड-19 की दूसरी लहर के साये से निकल रही है। लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इकोनॉमी को तगड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से 74 डॉलर के पार चला गया है। सिर्फ इसी साल देखें तो जनवरी से अभी तक कच्चे तेल के दाम में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन, राहत की बात यह है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों से पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। दिल्ली के बाजार में मंगलवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।

42 दिनों में ही 11.52 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

ऐसा देखा गया है कि अपने यहां जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम (झ्रूदत अगोत झ्रम) में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

करीब तीन महीने के बाद एक दिन सस्ता हुआ था डीजल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बीते 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। फिर दो महीने से भी ज्यादा समय तक इसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि, बीच में 15 अप्रैल को डीजल के दाम में 14 पैसे की मामूली कटौती हुई थी। चुनाव बीतने के बाद बीते 4 मई से इसमें रूक-रूक कर बढ़ोतरी होना शुरू हुआ। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, उसी दिन डीजल के भी दाम बढ़ते है। लेकिन शुक्रवार, दो जुलाई 2021 को सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़े थे। डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। सोमवार, 5 जुलाई को भी सिर्फ पेट्रोल का दाम बढ़ा जबकि डीजल स्थिर रहा। सोमवार, 12 जुलाई को तो पेट्रोल कीमत बढ़ने के बावजूद डीजल के दाम में कमी हुई। उसके बाद 15 जुलाई को इसके दाम बढ़े तो 17 जुलाई को सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी।

कच्चे तेल के बाजार में इस सप्ताह भी तेजी

भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे कोविड-19 की दूसरी लहर के साये से निकल रही है। लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इकोनॉमी को तगड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से 74 डॉलर के पार चला गया है। सिर्फ इसी साल देखें तो जनवरी से अभी तक कच्चे तेल के दाम में करीब 45 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। अमेरिकी बाजार में सोमवार को कारोबार की समाप्ति के समय ब्रेंट क्रूड (ाहू ण्ल्) 74.50 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। यह पिछले सप्ताह के शुक्रवार की कीमत के मुकाबले 0.40 डॉलर ज्यादा है। इसी तरह वहां यूएस वेस्ट टैक्सास इंटरमीडियएट या डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 72.11 डॉलर पर बंद हुआ था।

हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार

अगले महीने से शुरू होगा उत्पादन, प्रतिदिन एक लाख लीटर उत्पादन करने की क्षमता

यमुनानगर। एजेंसी

चीनी मिल के वेस्ट से एथेनॉल बनाने का हरियाणा का पहला सबसे बड़ा प्लांट यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में लगकर तैयार है। बस अब इंतजार है इसके चलने का। अगस्त से इस प्लांट में उत्पादन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। इस प्लांट में हर दिन एक लाख लीटर एथेनॉल बनेगी। 60 हजार लीटर प्रतिदिन की प्रोडक्शन देने वाला एथेनॉल का एक प्लांट शाहाबाद और दूसरा पानीपत में लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनसे उत्पादन शुरू होने में वक्त लगेगा। यमुनानगर में लग रहे प्लांट से बनने वाले एथेनॉल को पेट्रोल-डीजल में मिक्स किया जाएगा। इससे कच्चे तेल के आयात का बोझ कम होगा, वहीं इसके तेल में मिक्स होने पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 35 फीसदी तक की कमी लाई जा सकेगी। यमुनानगर के शुगर मिल में गन्ने के रस से मिलने वाले शीरा से एथेनॉल तैयार होगा। इस प्लांट पर करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च आया है।

2030 तक 20 फीसदी मिक्सिंग

एथेनॉल पेट्रोल-डीजल में मिक्स किया जाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन देश में अभी कम होने पर इसे 5 प्रतिशत ही मिक्स किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का और 2030 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है क्योंकि नियम अनुसार तेल में एथेनॉल 22 फीसदी तक मिक्स किया जा सकता है। एक्सपर्ट की मानें तो एथेनॉल मिलाने पर पेट्रोल की ज्वलनशीलता बनी रहती है। ऑक्टेन वेल्यू 2.5 प्रतिशत और ऑक्सीजन की क्षमता 3 प्रतिशत बढ़ जाती है। इससे पेट्रोल इंजन में 100 प्रतिशत जलता है और निकलने वाला धुआं 35 फीसदी तक कम प्रदूषण करता है।

अगले माह शुरू होगा उत्पादन

शुगर मिल के सीनियर वाइस प्रेजीडेंट केन डीपी सिंह ने बताया कि प्लांट तैयार है। अगले माह से इससे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। हर दिन हम एक लाख लीटर एथेनॉल तैयार करेंगे। यह प्लांट हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट होगा। यहां पर तैयार होने वाला एथेनॉल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर ऑयल कंपनियों को जाएगा।

अभी मिल से शीरे की डिस्टलरी व कैमिकल प्लांटों में सप्लाई

फिलहाल प्रदेश की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल से शीरा विभिन्न डिस्टलरी, कैमिकल प्लांट और ओपन मार्केट में बेचा जाता है। शुगर मिल यमुनानगर में लगे एथेनॉल प्लांट से एथेनॉल ऑयल कंपनियों को जाएगा। यह सरकार के अंडर होगा कि वह किस कंपनी को इसे सप्लाई कराती है। मिल में अभी 150 से 166 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हर सीजन में होती है। इससे लाखों लीटर शीरा निकला है।

कारगिल विजय दिवसः शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में पेप्सिको इंडिया लाई लिमिटेड एडिशन कैन

नई दिल्ली। आईपीटी

पेप्सिको इंडिया ने कारगिल दिवस पर भारत के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में सीमित संस्करण के कैन पेश किए हैं। पेप्सिको इंडिया ने एक बयान में कहा कि सीमित संस्करण के कैन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी से प्रेरित हैं, जिन्हें कारगिल के 'शेरशाह' के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने कंपनी के स्लोगन 'ये दिल मांगे मोर' को अपने मिशन की सफलता को दर्शाने के लिए चुनकर अमर कर दिया। बयान में आगे कहा गया, ''सीमित संस्करण के कैन में एक क्यूआर कोड भी होता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता कैप्टन विक्रम बत्रा को पेप्सी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि देख सकेंगे।'' इस श्रद्धांजलि में कारगिल शहीद के जुड़वां भाई विशाल बत्रा ने अपने भाई के जीवन और उनकी वीरता की कहानी को याद किया है।

कब से खरीद सकेंगे ये कैन

पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि 'ये दिल मांगे मोर' वाक्यांश जो हमेशा पेप्सी का पर्याय रहा है, ने तब एक नया अर्थ लिया जब कैप्टन बत्रा ने इन पंक्तियों को बोला। कंपनी ने कहा कि सीमित संस्करण अगस्त में चुनिंदा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगा।

तेल और गैस को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

हर दिन बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस खास फैसले से तेल की कीमतों से आम जनता को राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाये रखने के लिये कोई योजना विचाराधीन नहीं है और अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों का निर्धारण वैश्विक बाजार में चल रहे रेट के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ईंधन की कुल जरूरतों का करीब 85 फीसदी दूसरे देशों से आयात करता है और वैश्विक बाजार में कीमतों का निर्धारण तेल का आयात उत्पादन और निर्यात करने वाले देश करते हैं।

एकसमान बनाए रखने के लिए नहीं है कोई योजना

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाये रखने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, '' ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।'' उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (मूल्य वर्धित कर), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से संप्रग सरकार के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 32 रूपये लिये जाते हैं और इसका उपयोग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने के अलावा लोगों को निःशुल्क टीका लगाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि में किया जाता है।

एमएसएमई कंपनियों को 45 दिन में बकाये का भुगतान कर देगा केंद्र

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र एमएसएमई का सभी बकाया भुगतान 45 दिनों में कर देगा। एमएसएमई के बकाया भुगतान के मामले में केंद्र सरकार का यही रुख है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की पहली लहर के बाद से ही एमएसएमई नकदी की संकट के जूझ रहे हैं। बकाए के भुगतान से एमएसएमई की नकदी की समस्या दूर होगी। वहीं, एमएसएमई के पास नकदी आने से अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी तेज होगी। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 फीसद है।

सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (पीएसयू) और केंद्रीय विभाग पर एमएसएमई के बकाया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के दौरान यह आश्वासन दिया। बाद में वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिये भी बताया कि केंद्र 45 दिनों में एमएसएमई का पूरा बकाया भुगतान कर देगा।

उन्होंने संसद में कहा कि एमएसएमई का बकाया काफी गंभीर मामला है और इस मुद्दे पर पूर्व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी के साथ चर्चा की गई थी। गडकरी ने एमएसएमई के बकाए पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री से इस मसले पर बात की थी।

सीतारमण ने कहा कि पिछले साल से केंद्र सरकार अपने सभी विभागों के बकाए की समीक्षा कर रही है जिन्हें एमएसएमई को भुगतान करना है। इनमें केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां भी शामिल हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बकाया भुगतान के नियम के मुताबिक 45 दिनों की समय-सीमा का उल्लंघन नहीं हो। एमएसएमई मंत्रालय पिछले डेढ़ वर्षों में बकाया भुगतान में तेजी के लिए कई बार वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुका है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी केंद्रीय विभागों को एमएसएमई के भुगतान को लेकर चुस्त रहने के लिए कहा जा चुका है। राज्यों को जीएसटी भुगतान के संबंध में वित्त मंत्री ने बताया कि इस संबंध में अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी। उन्होंने कहा कि जब हम सरकारी बकाया की बात करते हैं तो उनमें केंद्र के साथ केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां, राज्य सरकार और उनकी कंपनियां भी शामिल होती हैं।

डॉटपे ने 'फ्री डिलीवरी' पहल की घोषणा

व्यापारियों को डिलीवरी चार्ज नहीं चुकाना होगा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

महामारी के दौरान इन स्टोर में खरीदारी में गिरावट के साथ ऑन लाइन ऑर्डर और रिमोट डिलीवरी कई भारतीय व्यापारियों के लिए कमाई का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। फिर भी अधिकांश भारी कमीशन और डिलीवरी चार्ज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और यह भुगतान सर्विस प्रोवाइडर्स को होता है। इस मुश्किल समय में यह निगेटिव मार्जिन होता है। इस समस्या को हल करने के लिए गुड़गांव स्थित ओ2ओ कॉमर्स प्लेटफॉर्म डॉटपे ने व्यवसायों के लिए एक 'फ्री डिलीवरी' पहल की घोषणा की है जिसमें रेस्तरां, किराना स्टोर, एफएंडवी (ईन्) व्यापारी, मांस और पोल्ट्री की दुकानें और कंज्यूमेबल्स बेचने वाले अन्य विक्रेता शामिल हैं।

डॉटपे ऑन बोर्डिंग के समय व्यापारियों से एकमुश्त सदस्यता शुल्क लेना जारी रखेगा, पर इस पहल के एक हिस्से के तौर पर फ्री डिलीवरी का लाभ व्यवसायों की ओर से किए गए प्रारंभिक निवेश को खत्म करने में एक वरदान साबित होगा। सब्सक्रिप्शन पैकेज के आधार पर मर्चेंट 250 तक फ्रीडिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपभोक्ता जल्द ही ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा को हाथ से जाने न दें, डॉटपे की पेशकश इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

इस पहल पर डॉटपे के सह-संस्थापक और सीईओ श्री शैलाज नाग ने कहा, 'यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। कोविड-19 की तीसरी लहर किसी भी समय आ सकती है और लगातार डर में रह रहने वाले लोगों के लिए अपने सेफ ज़ोन से बाहर कदम रखना मुश्किल होरहा है। ऑनलाइन शॉपिंग उनके लिए एक मात्र राहत लगती है और डॉटपे में हमारा मानना है कि इन स्थानी यव्यवसायों को कठिन समय से बचने में मदद करने का यह हमारा एकमात्र मौका है। हमने हमेशा इस इकोसिस्टम के विकास की दिशा में अपने प्रयास किए हैं और इस वजह से हमने व्यापारियों/रिटेलर्स को फ्री डिलीवरी सेवा प्रदान करने की इस पहलको शुरू किया है।' कंपनी पिछले साल महामारी की पहली लहर के बाद से कॉन्टेक्ट लेस समाधानों के अपने सूट के माध्यम से ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का समर्थन कर रही है, जिस से उन्हें सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहकों से जुड़कर अपने ऑपरेशन फिर से शुरू करने में सहायता मिल रही है। अभी हाल ही में डॉटपे के ऑर्डर डायरेक्ट अभियान ने पूरे भारत में लोगोंको रेस्तरां से सीधे ऑर्डर करने और महामारी के दौरान अपने स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया।

लाईफस्टाईल ने सीज़न की सबसे बड़ी सेल की घोषणा

अग्रणी फैशन ब्रांड्स पर 50 प्रतिशत तक की छूट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिए भारत के अग्रणी फैशन डेस्टिनेशन, लाइफस्टाइल ने अपनी बहुप्रतीक्षित सेल की घोषणा की। जिसमें यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स पर 50 प्रतिशत तक या उससे भी ज्यादा छूट प्रदान कर रहा है। लाइफस्टाइल सेल में शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को इन-स्टोर एवं ऑनलाइन पर सर्वश्रेष्ठ डील्स मिलेंगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों को लाईफस्टाईल स्टोर्स और लाईफस्टाईल मोबाईल ऐप्स से कम से कम 5000 रु. की खरीद करने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा।

लाइफस्टाइल सेल फैशन प्रेमियों के लिए बहुत आकर्षक होगा। उन्हें यहां पर विभिन्न श्रेणियों व ब्रांड्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर शानदार ऑफर मिलेंगे। स्टोर्स पर ग्राहक फैशन ब्रांड्स, जैसे फोर्सा, जिंजर, मेलाँज़, कैप्पा, कोड, बोसिनी, फेम फॉरएवर, जूनियर्स आदि का लाईफस्टाईल का सफल पोर्टफोलियो एवं अनेक अग्रणी ब्रांड्स, जैसे जैक एंड जोन्स, वेरो मोडा, ओनली, मेबेलीन, लैक्मे, टाईटन, टौमी हिलफिगर, लेविस, लुई फिलिप आदि देख व खरीद सकेंगे। मेन्सवियर, किड्सवियर और वूमेंस वियर में वेस्टर्न व एथनिक, ब्यूटी एवं मेकअप, वॉचेस , फ्रैग्रेंस, फुटवियर, हैंडबैग्स एवं एक्सेसरीज़ आदि के साथ ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ ट्रेंड्स आकर्षक मूल्यों में मिलेंगे। अब आप अपने पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन से शॉपिंग कर अपनी वारड्रोब को स्टाईलिश मेकओवर दे सकते हैं। आपको यहां पर लेटेस्ट ट्रेंड्स, आकर्षक ऑफर एवं बेहतरीन डील मिलेंगे। लाईफस्टाईल सेल सभी लाईफस्टाईल स्टोर्स पर ऑनलाइन पर और एंड्राइड एवं आईफोन यूज़र्स के लिए एंड्राइड ऐप पर उपलब्ध होगी। लखनऊ में लाइफस्टाइल स्टोर वन अवध सेंटर में और फीनिक्स पैलेसियो, गोमती नगर स्थित है। लाइफस्टाइल सेल सभी लाइफस्टाइल स्टोर्स पर ऑनलाइन और एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध लाइफस्टाइल ऐप पर मान्य होगी। इंदौर में लाइफस्टाइल स्टोर सी21 मॉल, एबी रोड में स्थित है।

टैक्स कम कर पेट्रोल-डीजल की बिक्री बढ़ाने से होगी राजस्व की भरपाई

भोपाल। एजेंसी

पेट्रोल पर टैक्स वसूली के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। पेट्रोल- डीजल बिक्री के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि टैक्स कम करके बिक्री बढ़ाकर राजस्व की भरपाई की जा सकती है। वहीं, टैक्स कम करके मंहगाई पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। मालूम हो, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 31.55 रुपये प्रति लीटर वैट के अलावा साढ़े चार रुपये सरचार्ज भी वसूला जा रहा है। डीजल पर वैट की वसूली के मामले में राहत है और मध्य प्रदेश से ज्यादा टैक्स राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में है। डीजल पर मप्र 21.68 रुपये वैट वसूलता है। वहीं, केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर का निश्चित उत्पाद शुल्क लगाती है। पेट्रोल-डीजल बिक्री के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम थीं, तब टैक्स बढ़ाकर सरकार अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करती थी। अब पेट्रोल-डीजल की कीमतें अधिक होने से टैक्स कम कर बिक्री बढ़ाई जा सकती है। वे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में डीजल की खपत कम हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र से आने वाले वाहन वहीं से डीजल भरवा रहे हैं। यदि सरकार टैक्स कम कर दे तो कीमतें कम रहेंगी और अन्य राज्य के वाहन यहां से पेट्रोल-डीजल लेंगे। इससे बिक्री बढ़ेगी और राजस्व में कमी नहीं आएगी।

पेट्रोल-डीजल पर अधिक टैक्स

सरकार की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है। अन्य मद से राजस्व वसूली में कमी की भरपाई सरकार पेट्रोल या डीजल से कर रही है। इस पर टैक्स कम कर सरकार प्रदेश स्तर पर महंगाई पर नियंत्रण कर सकती है। **- मिलिंद शर्मा, अधिवक्ता व कर सलाहकार**

News यू केन USE

मंडाविया का देश के कच्चे माल से उर्वरक उत्पादन पर जोर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने फसलों के लिए डीएपी जैसे पोषक (न्यूट्रिएंट) उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में ही फॉस्फेटिक रॉक और पोटाश के भंडार के दोहन पर जोर दिया है। मंत्री ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार कार्रवाई योजना के साथ तैयार है। केंद्र उर्वरक बनाने में काम आने वाले खनिज संसाधनों से संपन्न राज्यों के साथ बातचीत शुरू करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंडाविया देश में उर्वरक विनिर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के आकलन को बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के कच्चे माल के जरिये उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। अभी भारत डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) जैसे उर्वरकों के उत्पादन को कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया चार पैसे चढ़कर 74.43 पर पहुंचा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे बढ़कर 74.43 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मासिक सौदे पूरे होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 74.44 पर खुली, और फिर बढ़त के साथ 74.43 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले चार पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.47 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़कर 92.46 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.47 प्रतिशत बढ़कर 74.83 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था।

एनटीपीसी आरईएल को मप्र के शाजापुर सौर पार्क में 325 मेगावॉट की परियोजनाएं मिली

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कहा कि उसकी शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (आरईएल) को मध्य प्रदेश के शाजापुर सौर पार्क में 325 मेगावॉट की सौर परियोजनाएं मिली हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल मध्य प्रदेश के शाजापुर सौर पार्क में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) की विजेता बनकर उभरी है। एनटीपीसी रिन्यूएबल्स ने क्रमशः 105 मेगावॉट और 220 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं हासिल की हैं। इसके लिए कंपनी ने क्रमशः 2.35 रुपये प्रति किलोवॉट (या प्रति यूनिट) और 2.33 रुपये प्रति किलोवॉट की सबसे कम बोली लगाई।

युवा स्टेशनरी का नया अभियान

'गेट वेल सून इंडिया'

रचनात्मकता के माध्यम से सकारात्मकता और जागरुकता को बढ़ावा देगा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

अब जब देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर चुका है, अब यह सभी के लिए जरूरी है कि हम एहतियात बरतें और उन लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें, जो इस समय भी कोविड-19 से पीड़ित हैं। नवनीत एजुकेशन के घराने से घरेलू स्टेशनरी ब्रैंड युवा ने बच्चों को महामारी के प्रभाव के संबंध में शिक्षित करने और यह बताने के लिए कि यह किस तरह हम पर अपना प्रभाव डालता है, एक कैंपेन 'गेट वेल सून इंडिया' लॉन्च किया है। जहां बच्चे देश के लिए गेट वेल सून कार्ड बनाते दिखेंगे। ये कैंपेन जहां बच्चों की अभिव्यक्ति को उभारेगी, वहीं लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देगी।

यह कैंपेन एक शक्तिशाली संदेश देता है कि कोरोना वायरस को हराना एक समाज के तौर पर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस कैंपेन में हम लोगों (भारतीयों) से भारत को जल्द ठीक करने में मदद करने की अपील की गई है। यह कैंपेन फेस मास्क पहनने की अहमियत पर जोर देता है। जितनी बार हम हाथों को धो सकते हों, हमसे हाथ धोने की अपील की गई है। साथ ही कोरोना के संबंध में कोई अफवाह न तो फैलाने और न ही उस पर विश्वास करने की अपील भी की गई है। अंत में यह अभियान हमें यह संदेश देता है कि हमें देश में चल रहे टीकाकरण अभियान में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, जो कोरोनावायरस के खिलाफ लोगों में इम्यूनिटी विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इस कैंपेन को एएनटीएस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने डिजाइन किया है और प्रोड्यूस किया है। युवा के चीफ स्?ट्रैटेजी ऑफिसर और प्रवक्ता अभिजीत सान्याल ने इस कैंपेन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, 'बच्चों और नौजवानों को ध्यान में रखकर एक ब्रैंड के रूप में युवा की परिकल्पना की गई थी। क्रिएशन हमारी ब्रैंड फिलॉसफी है। यह कैंपेन कोरोना से पीड़ित और तनाव से जूझ रहे हमारे साथी नागरिकों में एक उम्मीद का संचार करती है। हम इस मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं। अगर हम अपने संपर्क के माध्यम से सकारात्मकता और आत्मविश्वास लोगों में कायम करने में सफल हो पाए तो हम निश्चित रूप से यह कह सकेंगे कि हमने इस मुश्किल समय में कुछ योगदान दिया है। हमें काफी उम्मीद है कि हमारा मैसेज भी हमारे प्रॉडक्ट्स की तरह लोगों तक आसानी से पहुंचेगा।

भारत का पहला कस्टमाइज़्ड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और वेलनेस ब्रांड, वैदिक्स्

छोटे शहरों में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पहल शुरू की

हैदराबाद। आईपीटी नेटवर्क

भारत का पहला कस्टमाइज़्ड मॉडर्न आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और वेलनेस ब्रांड, वैदिक्स्, इंडिया के सभी प्रमुख रीजनल बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ब्रांड अपनी दोहरी मार्केटिंग स्ट्रैटिजी के द्वारा रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक साथ पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। हैदराबाद स्थित एक कस्टमाइज्ड आयुर्वेद ब्यूटी टेक स्टार्टअप, वैदिक्स्, हाइपर कस्टमाइज्ड हेयर और स्किन केयर रिजीम डिजाइन कर रहा है, ताकि एआई (AL) और आयुर्वेद दोनों की विशेषताओं का हमारी स्किन और हेयर की समस्याओं में भरपूर फायदा मिल सकें। टेक ब्यूटी ब्रांड हैदराबाद के सबसे बड़े कंज्यूमर टेक स्टार्टअप्स में से एक होने के साथ-साथ 3 वर्षों के भीतर ही अपनी कैटेगरी में अग्रणी हो गया है।

इंकनट के सीईओ और को-फाउन्डर चैतन्य नल्लन ने कहा, 'हम एक ऐसे ब्रांड के रूप में बढ़ना चाहते हैं जहां आयुर्वेद को आधारशीला बनाकर हम साइंटिफ़िक और ब्यूटी के सभी क्षेत्रों में कुछ नया करके एक बेहतरीन केयर लोगों तक पहुंचा सकें। हमने अपने कस्टमर्स को हाइपर-पर्सनल देखभाल देने के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई है जो कि 30,000 घंटे से ज्यादा के इन्टेन्सिव रिसर्च, विशेषज्ञों के सहयोग तथा आयुर्वेद, हर्बल अर्क और एसेंशियल ऑइल्स से जुड़ी ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स भी प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं।'

इंकनट डिजिटल वैदिक्स् ब्रांड का ग्रुप होल्डिंग्स है। अपनी रीजनल मार्केट स्ट्रैटिजी के बारे में बात करते हुए, वैदिक्स् के बिजनेस हेड, जतिन गुजराती ने कहा, 'हमारे लगभग 65इ कस्टमर्स भोपाल जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे गैर-मेट्रो शहरों में भी स्थित हैं। आयुर्वेद की अच्छाइयाँ सभी को मालूम है, हम भारतीयों की जड़ों तक आयुर्वेद की विशेषताओं को पहुंचाना चाहते हैं ताकि सभी को किफायती मूल्य में सही और आवश्यक सोल्युशंस मिल सकें।

जॉब सीकर्स व एम्प्लॉयर्स का पसंदीदा प्लेटफार्म बना नौकरीवालाडॉटकॉम

देश की विभिन्न कंपनियों और जरूरतमंदों का भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

दुनियाभर में कोविड- 19 कहर बनकर बरपा है, और इसका सबसे बुरा असर युवा व कर्मचारी वर्ग पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5 फीसदी है जो कि शहरी इलाकों में 7.1 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 6.2 फीसदी तक पहुंच गई है। ऐसे में देश के भीतर रोजगार पैदा करना, सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि इंदौर स्थित नौकरीवालाडॉटकॉम के फाउंडर आरिफ खान ने इस चुनौती को आगे बढ़कर स्वीकारा है और अपनी संस्था के जरिए जरूरतमंद, काबिल हुनरमंदों को उनका सही स्थान देने में मदद कर रहे हैं। रोजगार को लेकर जारी मौजूदा संकट के बीच नौकरीवालाडॉटकॉम जॉब सीकर्स और एम्प्लायर के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। कुछ हद तक ही सही लेकिन आरिफ की यह कोशिश, सैकड़ों जरूरतमंदों को नई उम्मीद देने के साथ, कंपनियों को उनके काबिल कर्मचारी भी उपलब्ध करा रही है। इन कोशिशों के बदौलत वर्तमान में संस्था लगभग देशभर के सभी बड़े छोटे शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इस बारे में नौकरीवालाडॉटकॉम के सीईओ कम फाउंडर आरिफ खान बताते हैं, 'हम एंट्री-लेवल, मिडिल-लेवल के साथ-साथ टॉप-लेवल एक्जीक्यूटिव सर्विस के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य उद्यमी, आत्म-प्रेरित, गतिशील और योग्य पेशेवरों के एक समूह के साथ ग्राहक संतुष्टि शत प्रतिशत बना कर रखना है। हमारे पास पेशेवरों का एक अच्छा नेटवर्क है। नौकरीवालाडॉटकॉम को ऐसे लोगों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने करियर की संभावनाओं को मजबूत करना चाहते हैं। हम सीवी पर व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के साथ लेटर तैयार करने, संभावित इंटरव्यू प्रश्नों की तैयारी और तकनीकी व इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देकर एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश करते है, और इसी ने हमें सबसे भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर बना दिया है।'

डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया का फेस्टिव ऑफर

दुनिया भर में ग्राहकों को मिलेगा राखी की खुशियां मनाने का मौका

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

विश्व का अग्रणी इंटरनेशनल एक्सप्रेस सेवा प्रदाता डीएचएल एक्सप्रेस अपने ग्राहकों के लिये एक एक्सक्लूसिव ऑफर त्यौहार की खुशी मनाने के लिए लाया है। डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया ने अपने राखी फेस्टिव ऑफर की शुरुआत की है, ताकि ग्राहक इस मौके पर विदेशों में रहने वाले अपने परिवार और दोस्तोंक को राखी और तोहफों का सरप्राइज दे सकें। 26 जुलाई से ग्राहक राखी और तोहफों के इंटरनेशनल शिपमेंट्स पर न्यू नतम 50इ की छूट पा सकते हैं। यह छूट 0.5 किलो से 2.5 किलो और 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो और 20 किलो के वजन वाले राखी और तोहफों के इंटरनेशनल शिपमेंट के लिये देश में डीएचएल के 654 सर्विस पॉइंट्स पर मिल सकती है। ग्राहक दूसरे देशों में रहने वाले अपने प्रियजनों को मिठाई, स्नैक्सस, आदि जैसे तोहफे भेजने के लिये इस विशेष छूट का इस्ते माल कर सकते हैं। यह ऑफर 23 अगस्त 2021 तक वैध रहेगा। डीएचएल एक्सप्रेस इंडिया में सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट संदीप जुनेजा ने कहा, ''महामारी के कारण वर्चुअल बातचीत में बढ़ोतरी हुई है। यह फेस्टिव ऑफर हमारे ग्राहकों को सीमापार रह रहे उनके प्रियजनों से जुड़ने में थोड़ा फिजिकल टच देने का हमारा तरीका है। हम समझते हैं कि तोहफे देना राखी मनाने का एक जरूरी हिस्सा है और हम अपने ग्राहकों के जश्न को खास बनाने वाली टीम बनना चाहते हैं। इस प्रयास के जरिये डीएचएल इंडिया किफायती दामों पर अबाध सेवाएं प्रदान करना जारी रखना चाहता है और यह बात हमारे मूल्यक प्रस्तोव के अनुरूप है।'' यह ऑफर इस सीजन के दौरान तोहफों के लेन-देन में बढ़ोतरी को देखते हुए पेश किया गया है। इसमें विदेशों में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों का भी ध्यान रखा गया है। ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को शुभकामनाओं के प्रतीक भेजने के लिये 220 देशों और क्षेत्रों में डीएचएल एक्साप्रेस की पहुँच का फायदा उठा सकते हैं। इस ऑफर में एसएमएस और ईमेल द्वारा प्रोएक्टिव अपडेट्स के माध्यकम से शिपमेंट की पूरी विजिबिलिटी का आश्वासन भी है, ताकि दुनिया में कहीं भी बाधारहित डिलीवरीज सुनिश्चित हो सकें।

अधिक कॉबर्न उत्सर्जन वाली कंपनियों में निवेश पर दीर्घावधि में हो सकता है नुकसान:शोध

नयी दिल्ली। एजेंसी

लघु अवधि में अधिक कॉर्बन उत्सर्जन यानी फुटप्रिंट वाली कंपनियों में निवेश पर निवेशकों को अधिक प्रतिफल या रिटर्न मिल सकता है लेकिन दीर्घावधि में निवेशकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सरकारें ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को लेकर नियमन लागू कर देती हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी (आईआईटी-गुवाहाटी) तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान-बेंगलूर (आईआईएम-बेंगलूर) के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है। दो शीर्ष संस्थानों की टीमों ने कॉर्बन उत्सर्जन तथा इन कंपनियों में निवेश के संभावित जोखिमों के बीच संबंध स्थापित किया है। शोधकर्ताओं ने अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध बड़ी कंपनियों में से 200 से अधिक का व्यापक डेटा विश्लेषण किया और इसके निष्कर्ष एआरएक्सआईवी में प्रकाशित किए गए हैं। यह अमेरिका के कॉर्नवेल विश्वविद्यालय की टीम द्वारा तैयार एक शोध साझा करने का मंच है। कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन का आकलन करने के लिए प्रत्यक्ष जीएचजी उत्सर्जन और खरीदे गए जीएचजी उत्सर्जन (बिजली की खपत या गर्मी में) पर विचार किया गया। तीन सदस्यीय टीम के अनुसार, जैसे कि दुनिया एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ना चाहती है और हर जगह अर्थव्यवस्थाएं अपनी कॉर्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश कर रही हैं। ग्रीनहाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन पर भरोसा करने वाली कंपनियों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों (71.6 प्रतिशत) ने 2016-19 की अवधि में अपने कार्बन उत्सर्जन में गिरावट दिखाई थी। आईआईटी-गुवाहाटी के प्रोफेसर प्रतिम चक्रवर्ती ने कहा, 'यह पाया गया कि कार्बन फुटप्रिंट का कंपनियों के आकार और राजस्व के साथ सकारात्मक संबंध था। हालांकि, खर्चों के साथ सहसंबंध राजस्व के मुकाबले थोड़ा कम पाया गया।''

रिलायंस ने कर्मचारियों, परिजनों को कोविड के 10 लाख टीके लगाए, अब आम लोगों को भी टीके लगाएगी

नयी दिल्ली। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोविड के 10 लाख टीके लगवाये हैं। कंपनी ने जिन लोगों को टीके लगवाये हैं, उनमें आरआईएल की सहयोगी तथा भागीदार इकाइयों के कर्मचारी भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कंपनी अब आम लोगों को 10 लाख टीके लगाएगी। सरकार की तरफ से निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिये टीकाकरण की व्यवस्था की छूट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की परामार्थ कार्यों से जुड़ी रिलायंस फाउंडेशन ने अप्रैल में टीकाकरण शुरू किया।सूत्र के अनुसार 'मिशन वैक्सीन सुरक्षा' के तहत टीके की 10 लाख खुराकें लगायी जा चुकी हैं। कंपनी के 98 फीसदी कर्मचारियों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है। इसमें कर्मचारी, सहयोगी और संयुक्त भागीदार सदस्य और उनके परिजन, अस्थायी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 'वी केयर इनीशिएटिव' के तहत आम लोगों को 10 लाख टीके लगाएंगे। पिछले महीने कंपनी की सालाना आम बैठक (एजीएम)में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता एम अंबानी ने आम लोगों के लिए टीकाकरण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था, 'इस मिशन को राष्ट्रव्यापी आधार पर लागू करना एक बहुत बड़ा काम है लेकिन यह हमारा धर्म है, हर भारतीय के लिए हमारा कर्तव्य और सुरक्षा का हमारा वादा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक साथ, हम कर सकते हैं और हम इससे बाहर आएंगे।'' रिलायंस ने टीकाकरण के लिए देश भर में 171 सेंटर स्थापित किए हैं। रिलायंस फाउंडेशन अब एनजीओ (गैर-सरकारी संगठनों) के जरिए 10 लाख अतिरिक्त खुराक लगाएगी। ये टीके संयंत्र के पास के लोगों को और आम जनता को लगाये जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए कई पहल किये हैं। इसमें चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ ही पूरे देश में 2000 कोविड देखभाल बिस्तर की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

इंडसइंड बैंक का शुद्ध लाभ जून तिमाही में दोगुना बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में दोगुना बढ़कर 1,016.11 करोड़ रुपये रहा। खुदरा कर्ज और फंसे ऋण के बदले प्रावधान कम होने से बैंक का लाभ बढ़ा है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 510.39 करोड़ रुपये था।

इंडसइंड बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बैंक की कुल आय अप्रैल-जून 2021 तिमाही में बढ़कर 9,362.76 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 8,682.17 करोड़ रुपये थी। बैंक की ब्याज आय आलोच्य तिमाही में 7,574.70 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2020-21 की इसी तिमाही में 7,161.73 करोड़ रुपये थी। बैंक का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) यानी फंसा कर्ज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल ऋण के मुकाबले हल्का बढ़कर 2.88 प्रतिशत रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 2.53 प्रतिशत था। शुद्ध एनपीए हालांकि घटकर 0.84 प्रतिशत पर आ गया जो एक साल पहले 2020-21 की जून तिमाही में 0.86 प्रतिशत था।

फंसे कर्ज और आपात स्थिति के एवज में प्रावधान जून 2021 को समाप्त तिमाही में घटकर 1,844.02 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2020-21 की इसी तिमाही में 2,258.88 करोड़ रुपये था। बैंक के एकीकृत वित्तीय परिणाम में इंडसइंड बैंक, भारत फाइनेंशियल इनक्लूजन लिमिटेड (पूर्ण अनुषंगी कंपनी) और इंडसइंड मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सहयोगी कंपनी) के नतीजे शामिल हैं। एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दो गुना उछलकर 974.95 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 460.64 करोड़ रुपये था। बैंक की आय इस दौरान बढ़कर 9,355.77 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 8,680.92 करोड़ रुपये थी।

आरबीआई ने पूछा मास्टरकार्ड पर बैन लगने के बाद क्या है बैंकों का प्लान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों मास्टरकार्ड पर बैन लगाया था। तब से लेकर अब तक रिजर्व बैंक इस बात का इंतजार कर रहा है कि बैंक अपनी आगे की रणनीति के बारे में उससे बात करें। इस मामले से जुड़े तीन लोगों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि केंद्रीय बैंक ने तमाम बैंकों से पूछा है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड को लेकर उनकी क्या तैयारी है और वह किस तरह वीजा या रुपे जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने क्यों लगाया मास्टरकार्ड पर बैन?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जुलाई को मास्टरकार्ड पर नए कार्ड जारी करने को लेकर बैन लगा दिया था। इसकी वजह ये है कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी मास्टरकार्ड डेटा को भारत में ही रखने के नियम का पालन नहीं कर रही थी। अब रिजर्व बैंक तमाम बैंकों से पूछ रहा है कि मास्टरकार्ड पर बैन लगाने के बाद उनका आगे का क्या प्लान है। बैंकों को वीजा या रुपे पर तो जाना ही होगा, लेकिन वह कब तक ऐसा करेंगे इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है।

इन बैंकों पर पड़ेगा सबसे बुरा असर

मास्टरकार्ड पर बैन लगाए जाने से सिर्फ क्रेडिट कार्ड जारी करने की रफ्तार ही धीमी नहीं होगी, बल्कि सेविंग अकाउंट खोले जाने पर भी इसका असर देखा जा सकेगा। दरअसल, दोनों के ही लिए बैंकों को अब वीजा या फिर रुपे पेमेंट प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मास्टरकार्ड बैन का सबसे बुरा असर भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर पड़ेगा।

बैंकों को उम्मीद, हट सकता है बैन

बहुत से बैंक तो आगे की रणनीति बनाने में इसलिए भी ढिलाई दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मास्टरकार्ड पर लगा बैन हट सकता है। नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीएल बैंक और यस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड मास्टरकार्ड के हैं। वहीं एचडीएफसी के 45 फीसदी, आईसीआईसीआई के 36 फीसदी और एक्सिस बैंक के 35 फीसदी कार्ड मास्टरकार्ड के हैं। ऐसे में अगर बैन नहीं हटता है तो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं बैंकों को होगा।

सावन में कैसे करें शिव आराधना

महामारी के संक्रमण से बचने के लिए घर पर शिव पूजा करने से भी मिलेगा पूरा फल

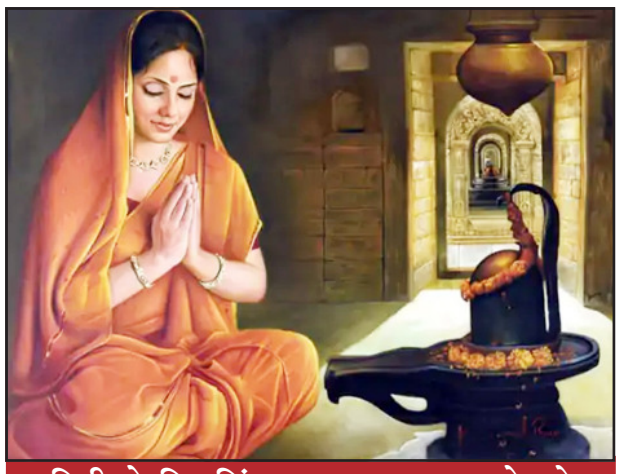

मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने को ही कहा जाता है पार्थिव शिवपूजन, ऐसा करने से हर तरह के दोष होते हैं खत्म

सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस बारे में शिव महापुराण में कहा गया है कि श्रावण मास का हर दिन पर्व होता है। इस दौरान की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है। जिससे हर तरह के दोष, रोग और परेशानियों से छुटकारा मिलने लगता है। इसलिए सावन महीने में शिव आराधना के लिए मंदिरों में भीड़ होने लगती है। लेकिन महामारी के संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही शिव पूजा करनी चाहिए। इस बारे में विद्वानों का भी कहना है कि घर पर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आराधना करने से पूजा का पूरा फल मिलता है।

घर पर ही कर सकते हैं शिवजी की पूजा

धर्म ग्रंथों के जानकार पुरी के डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि महामारी के संक्रमण से बचने के लिए मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही शिवलिंग का अभिषेक और पूजन किया जा सकता है। जिसके घर पर शिवलिंग न हो, वो आंगन में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं।

काशी विद्वत परिषद बनारस के मंत्री, डॉ. रामनारायण द्विवेदी का कहना है कि मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन करने को ही पार्थिव शिवपूजन भी कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी के किसी पत्थर को भी शिव रूप मानकर पूजा की जा सकती है। इस तरह शिव आराधना करने से भी पूजा का पूरा पुण्य फल मिलता है। बस ये सावधानी रखनी होगी कि पूरे सावन में एक ही शिवलिंग की पूजा हो और महीना बीत जाने के बाद पवित्र नदी में शिवलिंग प्रवाहित किया जाए।

सावन में शिव पूजा के खास दिन

सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए 8 दिन खास हैं। इनमें 26 जुलाई को पहला सावन सोमवार बीत जाने के बाद अब 2 अगस्त को दूसरा सोमवार आएगा। फिर 5 को गुरु प्रदोष, 6 को श्रावण शिवरात्रि, 9 को तीसरा सोमवार 16 को चौथा और सावन का आखिरी सोमवार रहेगा। इसके बाद 21 को शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की विशेष पूजा का भी विधान बताया गया है। इनके अलावा अगस्त महीने में 8 को हरियाली अमावस्या, 11 को हरियाली तीज और 22 को सावन महीने के आखिरी दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की भी परंपरा है।

घर पर ही आसान तरीके से हो सकती है पूजा

- सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद हाथ में जल लेकर शिव पूजा का संकल्प लें।
- इसके बाद ऊँ नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और पंचामृत से अभिषेक करें। इनके साथ ही जो भी चीजें उपलब्ध हो शिवलिंग पर चढ़ाएं।
- शिवजी को चंदन, चावल, फूल, बिल्वपत्र, धतूरा चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं। इसके बाद फल, मिठाई, दूध या जो भी उपलब्ध हो उसका नैवेद्य लगाएं।
- इसके बाद कर्पूर जलाकर आरती करें। फिर शिवजी का ध्यान करते हुए आधी परिक्रमा करें और प्रसाद बांट दें।

भक्ति का महीना

सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं अलग-अलग चीजें

शिव पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ऊँ नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन होता है शांत

शिव जी का प्रिय माह सावन शुरू हो गया है। 23 अगस्त को सावन माह की पूर्णिमा है। सावन माह की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। 23 अगस्त तक शिव पूजा के साथ ही दान-पुण्य भी जरूर करना चाहिए। शिवलिंग का पूजन करें और इसके बाद जरूरतमंद लोगों को धन-अनाज का दान करें। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार सावन माह में शिव पूजा करने पर भक्त के नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और मन शांत होता है। शिवपुराण में शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली कई चीजों का बारे में बताया गया है। शिव पूजा में चंदन, बिल्वपत्र, दूध, सफेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। इनके साथ अलग-अलग अनाज और फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा में ऊँ नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र - ऊँ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शिवलिंग पर चावल अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें चावल टूटे न हों। चावल चढ़ाने से धन संबंधी कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म हो सकती हैं। साथ ही, काले तिल, खड़े मूंग, लाल मसूर की दाल, चने की दाल, जौ भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जो लोग शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाते हैं और सावन में गेहूं का दान करते हैं, उनके घर में अन्न की कमी नहीं होती है। संतान सुख मिलता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।

शक्ति के बिना अधूरी शिव आराधना

सावन सोमवार की तरह मंगलवार भी खास, इस दिन गौरी पूजा के बिना नहीं मिलता शिव पूजा का फल

सावन महीने में हर हफ्ते की शुरुआत भगवान शिव और देवी पार्वती से होती है। सावन का सोमवार जितना खास होता है उतना ही महत्व मंगलवार का भी है। पुराणों में बताया गया है कि सावन महीने के मंगलवार को देवी पार्वती की पूजा और व्रत करना चाहिए। इससे हर तरह की परेशानियां खत्म होती हैं और सुख-समृद्धि बढ़ती है। इस तरह सावन महीने में हर हफ्ते के शुरुआती 2 दिन भगवान शिव और पार्वती को समर्पित होते हैं।

शक्ति के बिना अधूरी शिव पूजा

पुरी के ज्योतिषाचार्य और धर्मग्रंथों के जानकार डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि सोमवार को शिव पूजा का दिन माना जाता है। इसलिए लोक परंपरा में सावन सोमवार को बहुत खास माना जाता है। लेकिन मंगलवार का भी महत्व उतना ही है जितना सोमवार का है। सोमवार को की गई शिव पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब मंगलवार को देवी पार्वती की पूजा की जाए। क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि सावन महीने में देवी पार्वती के गौरी रूप की पूजा करनी चाहिए।

सावन मंगलवार की पूजा और व्रत

सावन महीने में सोमवार की तरह मंगलवार के दिन उपवास रहकर देवी पार्वती की गौरी रूप की पूजा करने की परंपरा है। इसका जिक्र स्कंदपुराण और विष्णुधार्मोत्तर पुराण में किया गया है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा कर के स्वर्णागौरी व्रत किया जाता है। जिससे दांपत्य सुख बढ़ता है और परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन देवी दुर्गा और हनुमान जी के उपासक भी व्रत और विशेष पूजा करते हैं। पुराणों के मुताबिक ऐसा करने से देवी दुर्गा और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। इनकी पूजा करने से कर्ज नहीं होता और रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं।

सावन में मंगला गौरी व्रत

सावन महीने के दौरान हर मंगलवार को देवी पार्वती की गौरी रूप में पूजा और व्रत करने का विधान है। मंगलवार और गौरी से मिलकर ही मंगला गौरी व्रत बना है। ये व्रत हर तरह का मंगल करता है इसलिए भी ये नाम पड़ा। मंगला गौरी व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे पति को पाने के लिए करती हैं। शादीशुदा महिलाएं दांपत्य सुख और समृद्धि की इच्छा से ये व्रत करती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन तृतीया तिथि यानी तीज का संयोग होने से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

शिव पूजा और दान का महीना:सावन में दूध और फलों का रस दान करने से खत्म होते हैं जाने-अनजाने में हुए पाप

सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। इसमें शिव पूजा के साथ दान और पेड़-पौधे लगाने का भी बहुत महत्व है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन महीने में दान से हर तरह का सुख, वैभव और पुण्य मिलता है। वहीं अन्य पुराणों में बताया गया है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ ही पूज्य पेड़-पौधे लगाने और उनका दान करने से शिवजी के साथ ही अन्य देवता और पितृ भी प्रसन्न होते हैं।

सावन मे दूध और फलों के रस का दान

धर्म ग्रंथों के जानकार पुरी के डॉ. गणेश मिश्र बताते हैं कि सावन महीने में किसी भी चीज का दान करने से कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस महीने में रूद्राक्ष, दूध, चांदी के नाग, फलों का रस और आंवला दान करने से जाने-अनजाने में किए पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही इस महीने में पौधारोपण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। डॉ. मिश्र बताते हैं कि जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की कृपा मिलती है क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है।

रुद्राक्ष दान करने से बढ़ता है सुख और ऐश्वर्य

सावन महीने में शिवजी का अभिषेक, शिवपुराण कथा पढ़ने-सुनने और मंत्र जाप के अलावा दान का भी बहुत महत्व है। सावन महीने में चांदी के सिक्के दान देने या चांदी से बने नाग-नागिन की मूर्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। शिवालयों में वैदिक ब्राह्मण को रुद्राक्ष माला का दान करने से सुख बढ़ता है।

पेड़-पौधे लगाने से खुश होते हैं पितृ और देव

श्रावण महीने में बिल्वपत्र, शमीपत्र, शिवलिंगी, अशोक, मदार और आंवले का पौधारोपण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनके साथ ही अनार, पीपल, बरगद, नीम और तुलसी लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं। पौधारोपण के साथ ही इन पेड़-पौधों का दान करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ऑडी की शुरूआत

लांच की तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

जर्मनी लक्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अपनी यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 3 इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑडी ई-ट्रॉन 50, ऑडी ई-ट्रॉन 55 और ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक 55 को लांच किया। आगे और पीछे अतुलनीय डायनमिक इलेक्ट्रिक मोटरों से सशक्त ऑडी ई-ट्रॉन और ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक पूरी तरह एक नया ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती हैं।

इस लांच पर ऑडी इंडिया के प्रमुख श्री बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, ''हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम भारत में ई-ट्रॉन ब्रांड को लांच कर रहे हैं। ई-ट्रॉन ब्रांड के तहत हम सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन इलेक्ट्रिक एसयूवी लांच करते हुए अपना इलेक्ट्रिफिकेशन सफर शुरु कर रहे हैं। ऑडी ई-ट्रॉन 50, ऑडी ई-ट्रॉन 55 और ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक 55 लक्जरी, 'शून्य उत्सर्जन, परफॉरमेंस और दैनिक उपयोगिता का उत्कृष्ट मेल हैं। इन तीन पेशकशों के साथ हमारे पास छोटे लेकिन बढ़ते लक्जरी एसयूवी स्पेस में हर किस्म के ग्राहक के लिए इलेक्ट्रिक वाहन है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना आसान बने इसके लिए हम कई लाभ व पैकेज प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें आफ्टर-सेल्स, चार्जिंग और ओनरशिप शमिल हैं।

श्री ढिल्लों ने आगे कहा, ''दुनिया भर में ऑडी ई-ट्रॉन और ऑडी ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी बनी हुई हैं। सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए स्पष्ट रोड मैप है बतौर ऑडी इंडिया हम इलेक्ट्रिक वाहनों का परिवेश विकसित करने के लिए समर्पित हैं। हमने ऐसे अनुबंध कर रखे हैं जो शुरु से अंत तक सभी पहलुओं को दायरे में लेते हैं जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने से लेकर ऐंड-ऑफ-लाइफ बैटरी रिसाइकलिंग तक शामिल हैं। भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है और ऑडी इंडिया इसके लिए तैयार है।''

नैनो यूरिया उत्पादन के लिये इफको,नेशनल फर्टिलाइजर्स,राष्ट्रीय केमिकल्स के बीच समझौता

नयी दिल्ली। एजेंसी

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने तरल नैनो यूरिया के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर सहकारी समिति इफको के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएफएल और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) ने तरल नैनो यूरिया की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत इफको बिना किसी रॉयल्टी के एनएफएल और आरसीएफ के तरल नैनो यूरिया की प्रौद्योगिकी हस्तातंरित करेगी। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया और रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन और अन्य संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, इफको किसानों के बीच नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ाने के लिए इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से उत्पादन बढ़ेगा जिससे आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित होगा और अधिक-से-अधिक किसान इसे अपनाएंगे। इससे किसानों के साथ-साथ सरकार के लिये सब्सिडी की बचत होगी। एनएफएल और आरसीएफ किसानों को नैनो यूरिया आपूर्ति बढ़ाने के लिये नये उत्पादन संयंत्र लगाएंगे। मंडाविया ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर देश के किसानों के हितों को ध्यान देने और देश को उर्वरक में आत्मनिर्भर बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ''इफको द्वारा बनाए गए नैनो यूरिया में देश में कृषि के लिए पासा पलटने वाला साबित होने की क्षमता है। भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।''

टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति पर बने रहने की उम्मीद

नयी दिल्ली। एजेंसी

टाटा मोटर्स ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि टेस्ला की भारत में अपने वाहनों को बेचने के लिए आयात शुल्क कम करने की मांग के बीच सरकार अपनी फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की नीति का लगातार पालन करेगी। ऑटो कंपनी की 2025 तक अपने घरेलू उत्पाद पोर्टफोलियो में 10 नए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) जोड़ने की योजना है। कंपनी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सरकार की नीति इस वर्ग के लिए अपने द्वारा पहले से शुरू की जा चुकी नीति के अनुरूप बनी रहेगी। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी पी बालाजी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संवाददाताओं से कहा, 'टाटा मोटर्स के दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने फेम 2 प्रोत्साहनों के माध्यम से, उस दिशा के लिए पात्रता मानदंड बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हैं जिसमें ईवी को अपनाने के लिए हमें तेजी से बढ़ना चाहिए। इसने इसने हमेशा सस्ती ईवी और साथ ही चरणबद्ध निर्माण योजनाओं के अनुसार स्थानीयकरण पर जोर दिया है।' उन्होंने कहा, 'मुझे यकीन है कि सरकार उस विशेष सोच और फेम2 के सिद्धांतों के अनुरूप काम करती रहेगी। हम सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं।'

कपास की महंगाई, ऊंचा आयात शुल्क सूती वस्त्र उद्योग लिए बड़ी चिंताः सिमा

कोयंबटूर। एजेंसी

दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन (सिमा) ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा 15 दिनों के भीतर कपास की दर प्रति कैंडी (355 किग्रा) और कपास पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क से सूती कपड़ा उद्योग भारी दबाव में आ गया है। सिमा के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि जनवरी 2021 से कपास की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इस महीने आसमान छू गई हैं। यहां तक कि सीसीआई ने जुलाई की शुरुआत से, कीमत 51,000 रुपये से बढ़ाकर 54,800 रुपये प्रति कैंडी कर दी है, जिससे बाजार में तेजी आई है।

अश्विन ने कहा कि गुजरात स्थित शंकर -6 कपास का बाजार मूल्य पिछले जनवरी में 43,300 रुपये था, जो अब बढ़कर 56,600 रुपये हो गया है, जो 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। उन्होंने बताया कि कपास की कीमतों में भारी वृद्धि न केवल उद्योग प्रभावित होगा और उसका मार्जिन कम होगा बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए परिधान और कपड़ा वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जो पहले से ही कोविड - 19 महामारी के दुष्प्रभावों से बोझिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बिक्री मूल्य असामान्य रूप से अधिक है। भले ही वहन लागत और उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखा जाए, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए सीसीआई कीमतों को लगभग 48,000 रुपये प्रति कैंडी के उचित स्तर पर बनाए रख सकता था।

उन्होंने कहा, ''कपास पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क का लाभ उठाते हुए, व्यापार जगत ने कीमतों की अटकलबाजी को बढ़ावा दिया है और कुछ किस्मों जैसे ईएलएस (एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल) कपास की घरेलू कीमतें पहले ही अंतरराष्ट्रीय मूल्य से अधिक हो गई हैं, जिससे हमारा उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो गया है।''

इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने सरकार से बाजार की धारणा को बदलने और सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला को और नुकसान से बचने के लिए तुरंत 10 प्रतिशत आयात शुल्क वापस लेने का आग्रह किया।

टोयोटा किर्लोस्कर सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर वारंटी बढ़ाएगी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने बुधवार को कहा कि वह अपने सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों (एसएचईवी) की बैटरी पर वारंटी बढ़ा रही है, जो अगस्त से प्रभावी है। एक बयान के मुताबिक कंपनी अपने सभी एसएचईवी मॉडलों - टोयोटा कैमरी और वेलफायर के लिए मौजूदा वारंटी, जो तीन साल या 100,000 किलोमीटर के लिए है, को बढ़ाकर आठ साल या 1,60,000 किलोमीटर (जो भी पहले हो) कर रहा है, जो एक अगस्त 2021 प्रभावी है। टोयोटा किर्लोस्कर ने कहा कि यह कदम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। टीकेएम के संयुक्त महाप्रबंधन (बिक्री और रणनीतिक विपणन) वी विसेलिन सिगामनी ने कहा, ''लंबी बैटरी वारंटी के जरिए हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को बढ़ाने वाले ग्राहकों को प्रत्साहित कर रहे हैं।''

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा एफएसएसएआई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मंगलवार को कहा कि वह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सूचना रिकॉर्डिंग की प्रणाली (ब्लॉकचेन) और मशीन लर्निंग जैसे अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की संभावना तलाश रहा है। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अरुण सिंघल ने कहा कि महामारी ने नियामक द्वारा नियमित तौर पर किये जाने निरीक्षण के कई पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए इस तरह की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये निरीक्षण आवश्यक हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उद्योग और शोधकर्ताओं से इस तरह के सरल उपकरणों के साथ आने का आग्रह किया जिनका नियामक उपयोग कर सके। सिंघल ने कहा, खाद्य नियामक सही जानकारी रखने के लिए ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की संभावनाओं की खोज कर रहा है।''

fssai
Food Safety and standards Authority of india

डोनेटकार्ट ने कोयला खनिकों को कोविड -19 की दूसरी लहर में दी मदद

दूसरी लहर से उबरने में संघर्ष कर रहे कोयला खनिकों को क्राउडफंडिंग से सहायता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर में लगाए गए लॉकडाउन में भारत के प्रतिष्ठित क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म डोनेटकार्ट ने नंद केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर 40 हजार से ज़्यादा कोयला खनिकों को खाने-पीने का ज़रूरी सामान दिलाने का सराहनीय काम किया है। कोविड -19 महामारी के चलते खनन गतिविधि बंद होने से धनबाद के हजारों डेली-वेज पर काम कर रहे कोयला खनिक मुश्किल में आ गए थे। वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से इसी पर निर्भर था। इनके परिवारों की दुर्दशा देखकर, डोनेटकार्ट और नंद केयर फाउंडेशन ने मिलकर फंड इकट्ठा किया ताकि खाने-पीने की ज़रूरी चीज़ें दी जा सकें।

इस फंडरेज़ प्रोग्राम में, डोनेटकार्ट ने अपने प्लेटफार्म पर एक अभियान चलाया जहाँ लोग अपने बजट के हिसाब से डोनेट कर सकते हैं। इस वेबपेज पर लोग किराना किट, अनाज, दालें, मास्क, सैनिटाइज़र आदि डोनेट कर सकते थे। किराना किट में गेहूँ का आटा, चावल, चना दाल, नमक, तेल, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर शामिल थे। नंद केयर फाउंडेशन ने डोनेटकार्ट और 25,000 से अधिक डोनरों के सहयोग से 2.3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की किराना किट जुटाई जो धनबाद और उसके आसपास 10000ह्र कोयला खनिकों के परिवारों में बाँटी गई। डोनेटकार्ट के सीईओ और को-फाउंडर अनिल कुमार रेड्डी का कहना है, 'हमने पहली लहर के दौरान हजारों परिवारों तक किराना किट पहुँचाई थी, और अब भी उनकी मदद करना जारी रखना चाहते हैं। कोयला खनिकों की दुर्दशा दयनीय है। नंद केयर फाउंडेशन के फाउंडर दीपक कुमार डोनेटकार्ट प्लेटफॉर्म के फंडरेज़ से मिले रिस्पांस से काफी संतुष्ट थे। 'जब ये कोयला खनिक चावल के एक-एक दाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, तो डोनेटकार्ट के साथ-साथ बहुत से डोनर आगे आए और मदद की।

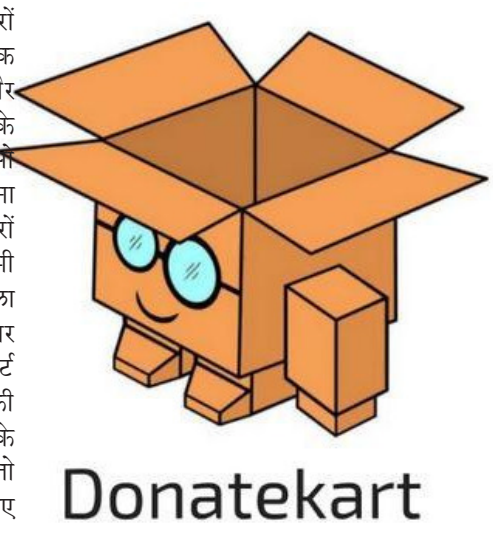

आधार बनवाने के बदल गए नियम, UIDAI ने दी जानकारी; आप पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। एजेंसी

आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बच्चों का आधार बनवाने की प्रक्रिया अब बदल दी है। यूआईडीएआई ने कहा कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल से डिस्चार्ज की स्लिप और माता-पिता में से किसी एक के आधार से बच्चे के बाल आधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

बदल गए आधार कार्ड के नियम

बाल आधार, आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है। लेकिन अब नए नियम के तहत पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आई स्कैन) की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। वहीं, बच्चे की उम्र पांच साल की होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट की आवश्यकता होगी।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

जरूरी दस्तावेजों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड आदि शामिल हैं। वहीं पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले दस्तावेजों में पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट / पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड आदि शामिल हैं।

एनरॉलमेंट सेंटर पर बनेगा आधार

एनरोलमेंट सेंटर पर पहचान का प्रमाण (POI), पते का प्रमाण (POA), रिश्ते का प्रमाण (POR) और जन्म तिथि (डीओबी) दस्तावेज जैसे जरूरी डॉक्यमेंट्स अपने साथ ले जाएं। केंद्र में मौजूद वहां के आधार अधिकारी से सभी दस्तावेजों की जांच कराएं। अगर आपका बच्चा पांच साल से ऊपर का है तो बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा। लेकिन पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल डेमोग्राफिक डेटा और चेहरे की पहचान की आवश्यकता होगी।

90 दिन में आ जाएगा बाल आधार

इस प्रक्रिया के बाद माता-पिता को उनके आवेदन के प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए एक एकनोलेजमेंट नंबर मिलेगा। उसके बाद 60 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस मिलेगा. बाल आधार कार्ड 90 दिनों के भीतर आपके पास पहुंच जाएगा।

ऐसे बनवाएं बच्चे का बाल आधार

1. बाल आधार बनवाने के लिए सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाएं।
2. अब यहां आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें।
3. अब इसमें जरूरी डिटेल, जैसे बच्चे का नाम और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी भरें।
4. अब आवासीय पता, इलाका, राज्य जैसी डेमोग्राफिक डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें।
5. आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन निर्धारित करने के लिए 'अपॉइंटमेंट' विकल्प पर क्लिक करें।
6. करीबी एनरोलमेंट सेंटर चुनें, अपना अपॉइंटमेंट तय करें और आवंटित तिथि पर वहां जाएं।

सेंसेक्स 135 अंक टूटा, वित्तीय शेयरों में गिरावट

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

बीएसई सेंसेक्स में बुधवार को 135 अंक की गिरावट आयी। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक में गिरावट के साथ बाजार नीचे आया। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 135.05 अंक यानी 0.26 प्रतिशत टूटकर 52,443.71 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 37.05 अंक यानी 0.24 प्रतिशत फिसलकर 15,709.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में दो प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ सर्वाधिक नुकसान में कोटक बैंक का शेयर रहा। इसके अलावा, डा. रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिउ, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक में भी प्रमुखता से गिरावट रही। दूसरी तरफ, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और बजाज फिनसर्व लाभ में रहने वाले शेयरों में शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी ने कहा, ''नियामकीय मुद्दों को लेकर चीन में प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव के साथ वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच घरेलू बाजार में गिरावट आयी।'' उन्होंने कहा कि इसके अलावा संपत्ति गुणवत्ता को लेकर चिंता से वित्तीय शेयरों में बिकवाली की गयी, जिससे मानक सूचकांक नीचे आया। हालांकि यूरोपीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख और गिरावट के बाद कम मूल्य पर शेयरों की लिवाली से बाजार दोपहर कारोबार में दिन के न्यूनतम स्तर से बाहर आया। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई और टोक्यो नुकसान में रहें जबकि हांगकांग और सियोल में तेजी रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में मध्याह्न कारोबार में सकारात्मक रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.76 प्रतिशत मजबूत होकर 74.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

एचसीसीबी इंडिया केस चैलेंज के पहले संस्करण के लिए देश भर के 17 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे मुकाबला

नई दिल्ली। एजेंसी

2021- इंडिया केस चैंलेंज के पहले संस्करण में शीर्ष तीन अवॉर्ड पाने के लिए देश के कई मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग संस्थानों के 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आपस में मुकाबला करेंगे। इस चैलेंज का आयोजन भारत की शीर्ष एफएमसीजी कंपनियों में से एक हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस (एचसीसीबी) द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल और वर्चुअल रुप से इनेबल इस केस स्टडी चैलेंज का उद्देश्य एचसीसीबी बिजनेस के वास्तविक जीवन परिदृश्य से मामलों को प्रोत्साहन देना है, जिनका उपयोग मैनेजमेंट और बिजनेस शिक्षा में टीचिंग टूल्स के रुप में किया जा सकता है। यह प्रतियोगिता 20 अगस्त तक चलेगी और इसमें स्टूडेंट्स एलिमिनेशन के कई स्तरों से होकर गुज़रेंगे। इस प्रतियोगिता में आखिरकार फाइनल तीसरे राउंड के लिए शीर्ष 5 टीमें अपनी जगह बना पाएंगी जहां प्रत्येक टीम को एचसीसीबी की लीडरशिप टीम को एक व्यापक बिजनेस प्लान प्रस्तुत करना होगा। विजेता टीम को प्री-प्लेसमेंट इंटरव्यूज के साथ 3 लाख रुपए प्राप्त होंगे जबकि पहले रनर-अप को प्री-प्लेसमेंट इंटरव्यूज के साथ 2 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं दूसरे रनर-अप को प्री-प्लेसमेंट इंटरव्यूज के साथ 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। एचसीसीबी इंडिया केस चैंलेंज का उद्देश्य है तेज़ गति से और लगातार बदल रही बिजनेस की दुनिया में विशिष्ट संस्थागत चुनौतियों के बारे में जागरुकता निर्माण करना। इस प्रतियोगिता में बी.टेक अंतिम वर्ष और पूर्व-अंतिम वर्ष और एमबीए और एमटेक के दोनों वर्षों के स्टूडेंट्स ने और इसके साथ ही एक साल के पूर्णकालिक एमबीए पीजीपीक्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है, चाहे उनकी विशेषज्ञता कोई भी हो। इंडिया केस चैंलेंज की शुरुआत करने के पीछे छिपे तर्क पर जोर देते हुए श्री कमलेश शर्मा, चीफ पब्लिक अफेयर्स एंड कम्यूनिकेशन्स ऑफिसर, एचसीसीबी ने कहा, 'हमारा मानना है कि बेस्ट आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं और हम इस प्रतियोगिता के ज़रिए युवाओं की शक्ति को उपयोग में लाना चाहते हैं। प्रतियोगिता की रुपरेखा कुछ इस प्रकार तैयार की गई है जिससे स्टूडेंट्स को उनकी विश्लेषणात्मक योग्यता का उपयोग करने, समस्याओं की गहराई तक जाने और चुनौतियों को संबोधित करने वाले सबसे योग्य समाधान तैयार करने के लिए सक्षम किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को बेहद मेहनत से तैयार एवं विकसित किया गया है और महामारी के बावजूद हमने पूरी तरह डिजिटल रुख अपनाते हुए इस कार्यक्रम का बाधारहित तरीके से कार्यान्वयन किया है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमें कुछ बेहद शानदार आइडिया मिलने की उम्मीद है।'

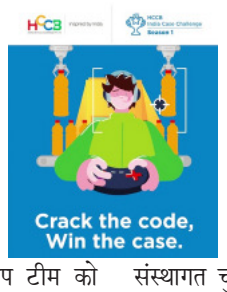

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।